



चुनाव आयोग के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती; ममता बनर्जी अदालत में मौजूद, वकीलों ने रखे तर्क

नई दिल्ली (विशेष प्रतिनिधि):

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी अदालत में मौजूद रहीं, जबकि उनकी ओर से नियुक्त वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में विस्तृत कानूनी दलीलें पेश कीं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि Election Commission of India के कुछ कदम संवैधानिक सीमाओं से परे हैं और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांतों को प्रभावित कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी अदालत

में उपस्थित रहीं और अदालत की अनुमति से संक्षेप में अपना पक्ष रखा, हालांकि पूरी कानूनी बहस उनके वकीलों ने ही की। न्यायालयी सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया पक्षकार की हैसियत से पक्ष स्पष्ट करने की श्रेणी में आती है, न कि वकील के रूप में बहस करने की। Supreme Court of India ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को आगे की विचारणा के लिए स्वीकार

करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय करने का संकेत दिया। अदालत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि इस मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है, जबकि आगामी सुनवाइयों पर राजनीतिक और सार्वजनिक हलकों की निगाहें टिकी हुई हैं।

राज्यसभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष का सरकार से सवाल, राजनीति पाटिल ने मांगी स्पष्टता

नई दिल्ली (संवाददाता):

राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का भारतीय किसानों के जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उच्च सदन में चर्चा के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते की घोषणा और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिक्रिया को

लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर यह समझौता किया है।



कांग्रेस सांसद राजनी पाटिल ने कहा कि यह संकेत दिया जा रहा है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा नहीं की, तो

इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ५०० अरब डॉलर की खरीद-फरोख्त का दावा किया है। ऐसे में संसद

और देश को यह जानने का अधिकार है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा की।

राजनी पाटिल ने ट्रंप के इस दावे पर भी सरकार से स्पष्टता मांगी कि भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा और अब रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल आयात करेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार ने देश के दीर्घकालिक सहयोगी को छोड़ने का निर्णय ले लिया है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद ऋताब्रत बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी आर्थिक विस्तारवाद के आगे समर्पण कर दिया है और

► पान ४ पे

रेल्वे परियोजनाओं को पूरा कराने पर सांसद बजरंग सोनवणे का फोकस; केंद्रीय रेल्वे मंत्री से की मुलाकात



नई दिल्ली: बीड लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित और अत्यंत आवश्यक रेल्वे परियोजनाओं को पूरा कराने पर सांसद बजरंग सोनवणे ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है। लंबित रेल्वे मार्गों के कार्य को गति देने के उद्देश्य से उन्होंने झरीश्रच्छराषणी वीथी में केंद्रीय रेल्वे, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री - िहुळपळ तरळीहपु से भेंट कर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मराठवाड़ा के परिवहन विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे रखे गए।

बैठक में मराठवाड़ा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धाराशिव-बीड-छत्रपति संभाजीनगर नई रेल्वे लाइन का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया गया। मार्च २०२५

में इस परियोजना के सर्वेक्षण के लिए ६ करोड़ रुपये की मंजूरी दिए जाने पर रेल्वे मंत्री का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही, परियोजना की डीपीआर शीघ्र पूरी कर प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वास्तविक कार्य शुरू करने की मांग की गई।

इसके अलावा, घाटानंदूर रेल्वे स्टेशन और आसपास के नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग दोहराई गई। इसमें औरंगाबाद-गुंर, बंगलुरु-नांदेड और नांदेड-पनवेल ट्रेनों को शामिल करते हुए कोविड-पूर्व के ठहराव पुनः शुरू करने की मांग रखी गई। इन सभी विषयों पर केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता

► पान ४ पे

गुटखा तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जब्त; १३.७४ लाख रुपये का माल कब्जे में



बीड, ४ (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू की अवैध दुलाई का भंडाफोड़ करते हुए उपअधीक्षक Pooja Pawar ने बुधवार सुबह कड़ी कार्रवाई की। इशशव के महालक्ष्मी चौक परिसर में जाल बिछाकर की गई इस कार्रवाई में गुटखा भंडार सहित स्कॉर्पियो वाहन, कुल १३ लाख ७४ हजार १४० रुपये का

मुद्देमाल जब्त किया गया।

बुधवार, ४ तारीख को मांजरसुंबा मार्ग से बीड की ओर एमएच-२३-एस-५५२२ नंबर की स्कॉर्पियो से बड़ी मात्रा में गुटखा ले जाए जाने की जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद महालक्ष्मी चौक पर सघन नाकाबंदी की गई। संदिग्ध वाहन रुकते ही एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि चालक को पुलिस ने

► पान ४ पे

चीन सीमा पर क्या हुआ, यह देश को बताया जाना चाहिए: हर्षवर्धन सपकाल

विपक्षी नेताओं को बोलने न देना मोदी की तानाशाही

मुंबई जमीर काजी चीन सीमा पर हुई गतिविधियों को लेकर विपक्ष के नेता

Rahul Gandhi ने लोकसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न उठाने का प्रयास किया, लेकिन मोदी सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है। इससे यह संदेह गहराता है कि भारत सरकार चीन के मुद्दे पर कोई सच्चाई छिपा रही है। विपक्ष के नेता को संसद में बोलने से रोकना अत्यंत निंदनीय है और यह संसदीय परंपराओं, नियमों और



मर्यादाओं का उल्लंघन है। यह आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष Harshvardhan Sapkal ने लगाया।

टिळक भवन में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपकाल ने कहा कि देश के पूर्व थलसेनाध्यक्ष Manoj Mukund Naravane ने अपनी पुस्तक फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी में चीन प्रकरण पर स्पष्ट रूप से लिखा है, जिससे यह उजागर होता है कि मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा

है। यही मुद्दा राहुल गांधी लोकसभा में उठाना चाह रहे थे। चीन से जुड़े सवाल पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और चीन सीमा पर वास्तव में क्या हुआ, यह जानने का अधिकार देश के हर नागरिक को है, लेकिन सरकार राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दे रही।

उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जब यह मुद्दा उठाया कि चीन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया है, तो मोदी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। यह सरकार की असहिष्णुता को दर्शाता है। विमान

► पान ४ पे

बीड शहर के लिए बिंदुसरा परियोजना से नई जलापूर्ति योजना लागू की जाए

भाजपा गटनेत्री डॉ. सारिकाताई क्षीरसागर के नेतृत्व में शिष्टमंडल की जिलाधिकारी से मांग

बीड (प्रतिनिधि):

शहर में मौजूदा अव्यवस्थित जलापूर्ति, हर साल गर्मियों में झेलनी पड़ने वाली पानी की किल्लत, आपूर्ति नियोजन की कमियां और आगामी गर्मी में संभावित संकट को देखते हुए बीड शहर के लिए बिंदुसरा परियोजना से नई अतिरिक्त जलापूर्ति योजना तुरंत प्रस्तावित कर कार्यों को गति देने की मांग की गई है। यह मांग भाजपा की गटनेत्री एवं नगरसेविका Dr. Sarika Kshirsagar के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मंगलवार (दि. ३)



को तत्वीशज्ञ गेहपीप से भेंट कर रखी। जिलाधिकारी ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है।

शिष्टमंडल ने बताया कि वर्तमान में बीड शहर को बिंदुसरा परियोजना से आंशिक जलापूर्ति हो रही है। इसे पूर्ण क्षमता से शुरू करने के लिए शहर से सटे घुमरे वस्ती और धानोरा रोड मार्ग से नई जलापूर्ति

योजना विकसित करना आवश्यक है। साथ ही, हाल ही में विकसित हुई बस्तियों के लिए अलग जल टंकियां और वितरण व्यवस्था

स्थापित की जानी चाहिए। शहर के कई हिस्सों में ८ से १५ दिनों के अंतराल पर पानी मिलने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शिष्टमंडल ने कहा कि शहर में पानी की उपलब्धता होते हुए भी उचित नियोजन के अभाव में आपूर्ति बाधित है। इसलिए सभी क्षेत्रों में नियमित और समान जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, अमृत अटल जलापूर्ति योजना १.० के अंतर्गत

शेष कार्यों को Maharashtra Jeevan Pradhikaran और संबंधित ठेकेदारों से शीघ्र पूरा कर सभी जोनों में वितरण व्यवस्था सुचारु करने के निर्देश देने की मांग की गई। साथ ही, महावितरण कंपनी का बीड नगरपरिषद पर लंबित बकाया एक जटिल मुद्दा बन गया है - इसे सुलझाकर जलापूर्ति योजनाओं में बाधा न आए, इसके लिए जिला प्रशासन से पहल करने का आग्रह किया गया।

इस अवसर पर मुख्याधिकारी शैलेष फडसे,

► पान ४ पे

२०२९ में बीड का विधायक अनिल जगताप ही होना चाहिए: मंत्री संजयजी शिरसाट

मंत्री संजयजी शिरसाट की उपस्थिति में चंपावती महोत्सव का भव्य उद्घाटन



बीड (प्रतिनिधि):

बीड के सांस्कृतिक क्षेत्र को नई दिशा देने वाला चंपावती महोत्सव इन दिनों पूरे महाराष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहा है और बीड की सकारात्मक पहचान बनाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभा रहा है - यह प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री ड्रपक्षरू डहळीरी ने किया। चंपावती महोत्सव के भव्य उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए मंत्री शिरसाट ने कहा, अनिलदादा जगताप ने राजनीति से इतर समाजसेवा, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर आम जनता का भला किया है। बीड की छवि बदलने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए २०२९ में बीड का विधायक अनिल जगताप ही होना चाहिए, ऐसा आद्वान उन्होंने उपस्थित बीडवासियों से किया।

अनिलदादा जगताप फाउंडेशन और बीड शिवसेना द्वारा आयोजित चंपावती महोत्सव- २०२६ - का भव्य उद्घाटन समारोह ४ फरवरी को उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर

पर शिवसेना की उपनेत्री संगीता ठोंबरे, दैनिक पार्श्वभूमि के संपादक गमंत भंडारी, दैनिक दिव्य लोकप्रभा के संतोष मानूरकर, दैनिक प्रारंभ के संपादक जालिंदर धांडे, जिलाप्रमुख सचिन मुळूक, स्वप्नील गलधर, महिला आघाड़ी संपर्क प्रमुख संगीता चव्हाण सहित शिवसेना, युवासेना महिला आघाड़ी, ओबीसी विघ्नवंटी सेना, एस.टी. कामगार सेना के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

उद्घाटन समारोह का प्रस्तावना भाषण चंपावती महोत्सव के संस्थापक अध्यक्ष प्रतीक कांबळे ने दिया। उन्होंने महोत्सव की संकल्पना से लेकर आयोजन तक की विस्तृत जानकारी साझा की। शिवसेना की उपनेत्री संगीता ठोंबरे ने अनिलदादा जगताप के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि चंपावती महोत्सव बीड के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। संपादक संतोष मानूरकर ने चंपावती महोत्सव चिरायु हो की शुभकामनाएं दीं, जबकि संपादक गमंत भंडारी ने

► पान ४ पे

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

डॉ.अजीत कुमार को CAPSES-२०२६ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार

छात्रों व युवा शोधकर्ताओं को विज्ञान और नवाचार की प्रेरणा देने वाले शोध का सम्मान

बीड (प्रतिनिधि): शहर की रामानुजन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक व निदेशक तथा आर२ई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार) ajit Kumar ने पर्यावरणीय सततता के लिए रासायनिक एवं भौतिक विज्ञान में अग्रणी शोध पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन CAPSES २०२६ में शोध-पत्र प्रस्तुति श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।	यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ३० और ३१ जनवरी २०२६ को एम.एस.पी. मंडल के बलभीम कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के रसायनशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में देश-विदेश के शोधकर्ता और प्राध्यापकों ने पर्यावरणीय सततता से जुड़े रासायनिक व भौतिक विज्ञान आधारित शोध प्रस्तुत किए। सम्मेलन को एम.एस.पी. के अध्यक्ष विधायक प्रकाश सोलंके, सचिव सतीश		चव्हाण और उपाध्यक्ष अमरसिंह पंडित का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आयोजन समिति में डॉ. ए.डी. चिंधे (आईक्यूएसी समन्वयक), प्रो. डॉ. बी.डी. कोकारे (उप-प्राचार्य) तथा	प्रो. डॉ. एस.एस. उंदरे (प्राचार्य एवं मुख्य संयोजक) शामिल थे। CAPSES-२०२६ में लगभग ३०० शोध-पत्र चयनित किए गए थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच डॉ. अजीत कुमार के शोध ने वैज्ञानिक गुणवत्ता, नवाचार और व्यावहारिक उपयोगिता के कारण विशेष ध्यान आकर्षित किया और उन्हें शोध-पत्र प्रस्तुति में प्रथम स्थान मिला। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, सिंथेटिक अपचर रडार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुप्रयुक्त	अनुसंधान में उनके अनुभव से इस उपलब्धि ने स्थानीय शोध परिवेश को नई प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक और अनुसंधान का समन्वय आवश्यक है। CAPSES-२०२६ में मिला यह सम्मान उनके शोध-यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो विद्यार्थियों और युवा शोधकर्ताओं को विज्ञान और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
---	---	--	--	---	---

७ और ८ फरवरी को होने वाली CTET परीक्षा को लेकर उम्मीदवार दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयारी करें: प्रो. अमर शेख

(प्रतिनिधि): केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (उदएड) आगामी ७ और ८ फरवरी को आयोजित होने जा रही है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयारी करने का आह्वान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पदवीधर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मोहम्मद अली जौहर महिला अध्यापक महाविद्यालय के प्राध्यापक Amar Sheikh ने किया है। उन्होंने कहा कि उदएड फरवरी २०२६ सत्र के लिए इस कोड और परीक्षा केंद्र में ले जाने योग्य वस्तुओं को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जांच में देरी या प्रवेश से वंचित किया जा सकता है, इसलिए सभी उम्मीदवारों को	सावधानी बरतनी चाहिए। CTET २०२६ परीक्षा ड्रेस कोड: क्या पहनें, क्या न पहनें उदएड देशभर के इच्छुक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। परीक्षा के दिन की छोटी-सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। इसी को देखते हुए Central Board of Secondary Education (CBSE) ने कपड़े, जूते-चप्पल, आभूषण और साथ ले जाने वाली वस्तुओं को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। कपड़ों से संबंधित दिशानिर्देश साथे, हल्के और आरामदायक कपड़े	पहनें हल्के रंगों के कपड़े उपयुक्त भारी कढ़ाई, बड़े बटन, बैज, कई ज़िप से बचे आधी बांह (हाफ स्लीव) की शर्ट/टॉप बेहतर साधे कपड़ों से सुरक्षा जांच जल्दी होती है जूते-चप्पल (पादत्राण) साधी चप्पल या सैंडल पहनें मोटे तले वाले जूते, धातु वाले जूते न पहनें हील्स या फैसी फुटवियर जांच में बाधा बन सकते हैं लंबी कतार में खड़े रहना पड़ सकता है, इसलिए आरामदायक जूते चुनें आभूषण और एक्सेसरी: क्या न पहनें अंगूठी, चेन, चूड़ियां, पायल, झुमके धातु की हेयर क्लिप या सजावटी वस्तुएं परीक्षा के दिन कोई भी आभूषण न पहनना सबसे	सुरक्षित धार्मिक/सांस्कृतिक पोशाक हिजाब, पगड़ी जैसे धार्मिक परिधान की अनुमति है ऐसे उम्मीदवारों को अतिरिक्त जांच के लिए पहले पहुंचने को कहा जा सकता है उदएड २०२६: परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं उडडए ने निम्न वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है: इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: मोबाइल फोन, स्मार्टवाच, फिटनेस बैंड, ब्लूटूथ, इयरफोन, कैमरा, पेन ड्राइव (बंद अवस्था में भी निषिद्ध) स्टेशनरी/अध्ययन सामग्री: किताबें, नोट्स, कागज़, केलकुलेटर, ज्योमेट्री बॉक्स व्यक्तिगत वस्तुएं: हैंडबैग, पर्स, वॉलेट, बेल्ट, गॉगल्स खाना/अन्य: कोई भी खाद्य पदार्थ या स्नैक्स निषिद्ध परीक्षा केंद्र में अनुमत वस्तुएं उदएड प्रवेश पत्र (प्रिंटेड) वैध फोटो	पहचान पत्र एक नीला या काला बॉलपॉइंट पेन पारदर्शी पानी की बोतल (यदि केंद्र अनुमति दे) जांच और प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश पत्र व पहचान पत्र की जांच हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच आवश्यकता होने पर मैनुअल जांच समय से पहले पहुंचना और निर्देशों का पालन करना आवश्यक नियम न मानने पर परिणाम CBSE से अपील की कि वे उदएड सूचना पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा की तैयारी करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा
--	---	---	---	--



गेवराईचे ज्येष्ठ पत्रकार काज़ी अमान यांना मानाचा व प्रतिष्ठेचा मूकनायक पुरस्कार मिळाल्याबद्दल ऑल इंडिया काँग्रेस संघटन महाराष्ट्रचे राज्याध्यक्ष काज़ी असद यांनी त्यांचा हृदयस्पर्शक केला. याप्रसंगी सामाजिक कार्यकर्ते काज़ी शौकत हे उपस्थित होते.

मुस्लिम नेताओं की मेहनत रंग लाई, गुजरात में लाखों मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुए

BJP ऑफिस से हजारों फॉर्म नंबर ७ भरवाए गए।

हबीब शेख, अहमदाबाद जिस तेजी से मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने गुजरात में रूलिंग पार्टी इग़ाज़ की मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करने और उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की नापाक साज़िश के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर और यहां तक कि दिल्ली में शिकायत की, उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों मुसलमानों के नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। मुस्लिम चड- इमरान खेड़ावाला, पूर्व MLA गयासुद्दीन शेख, जुनैद शेख, असलम सैकवाला, एडवोकेट इकबाल शेख द्वारा गुजरात इलेक्शन कमिश्नर हरित शुक्ला के सामने कई बार गुहार लगाने के बाद, आखिरकार इग़ाज़ वर्कर्स द्वारा फॉर्म ७ भरकर कैसिल किए गए १४ लाख मुस्लिम वोट वापस शामिल किए गए।	इग़ाज़ ने सिस्टैमैटिकली सिर्फ मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया और हजारों फॉर्म ७ जारी किए गए, जिस पर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने कड़ा एतराज जताया और इलेक्शन कमिश्नर को दिल्ली जाकर पेश करने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ, मुस्लिम संगठनों ने भी कोर्ट जाने की धमकी दी और आखिरकार मुसलमानों के नाम शामिल किए गए। एक समय में १४ लाख मुस्लिम वोटर्स समेत कुल १९ लाख वोटर्स को हटाया गया था, जो अब घटकर सिर्फ १.८९ लाख रह गए हैं। अहमदाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा २,१६,०८४ एप्लीकेशन आए हैं, इसके बाद सूरत में १,३१,१५३ और आणंद में ७८,७९० एप्लीकेशन आए हैं। दूसरे	ज़िलों में राजकोट में ७२,१४९ फॉर्म, भावनगर में ६३,११६ फॉर्म, वडोदरा में ५८,८२२ फॉर्म और कच्छ में ५४,२२१ फॉर्म आए हैं। सबसे कम, डांग ज़िले में ४,००१ एप्लीकेशन आए, जबकि नर्मदा में ७,३९७ और तापी में ८,०९६ एप्लीकेशन आए हैं। गुजरात में पिछले साल २७ अक्टूबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, जिसके बाद १९ दिसंबर को इसे जारी किया गया। लोगों को शुरू में क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए १८ जनवरी तक का समय दिया गया था, जिसे बाद में इलेक्शन कमीशन ने ३० जनवरी तक बढ़ा दिया था। सभी एप्लीकेशन की जांच और निपटारा १० फरवरी तक किया जाएगा।	फॉर्म ७ स्कैम में कुल वोटर्स की संख्या १२.५९ लाख से घटकर १.८९ लाख हो गई है। गुजरात में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व चड- गयासुद्दीन शेख ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को आखिरकार गुजरात में चल रहे ड्राफ्ट प्रोसेस का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य भर में इग़ाज़ और उससे जुड़े संगठनों के सदस्यों ने फॉर्म ७ भरकर वोटर्स के नाम कैसिल करने के लिए लाखों एप्लीकेशन जमा किए थे, जिनका डेटा इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर रहा है। २२ जनवरी को	गुजरात के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की कांग्रेस डेलीगेशन से मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ९.८८ लाख फॉर्म ७ मिले हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि पूरे राज्य से १.८९ लाख फॉर्म ७ जमा हुए, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने पूछा कि	गुजरात इलेक्शन ऑफिसर किसके प्रेशर में यह लुका-छिपी का खेल खेल रहे हैं! ? आपने खुद कहा था कि १२.५९ लाख फॉर्म ७ मिले हैं। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ १.८९ लाख फॉर्म-७ मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर फॉर्म ७ मिले हैं, तो बाकी १० लाख कहाँ गए? फॉर्म ७ का स्टेटस क्यों नहीं बताया गया? क्या वो १० लाख फॉर्म ७ कैसिल या रोक दिए गए हैं? ये जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसलिए कांग्रेस ने मांग की है कि एड्ज को सबसे पहले फॉर्म भरने वाले से आधार प्रूफ मांगना चाहिए। अगर आधार वैलिड है, तो डडज से वेरिफिकेशन के बाद गलत एक्शन लेकर वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना चाहिए।
---	--	--	---	---	---

पान १ से राज्यसभा में भारत-अमेरिका व्यापार... तेल की खरीद को लेकर ट्रंप द्वारा तय की गई सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता जॉन ब्रिटास ने कहा कि सरकार ने संसद को नजरअंदाज करते हुए सोशल मिडिया के माध्यम से समझौते की घोषणा की, जबकि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद को एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म से भी कमतर समझा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता अब्दुल वहाब ने कहा कि सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस समझौते की घोषणा की और भारत सरकार ने काफी बाद में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें १८ प्रतिशत की 'सब्सिडी' दी। ऑपरेशन सिंदूर की तरह उन्होंने हमारी सरकार को समय पर संबोधित किया। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि भारत ने अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने बताया कि चीन पर ३४ प्रतिशत, बांग्लादेश और वियतनाम पर २० प्रतिशत तथा इंडोनेशिया पर १९ प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, जबकि भारत पर केवल १८ प्रतिशत शुल्क है। ----- रेल्वे परियोजनाओं को पूरा कराने... से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों तथा नौकरीपेशा वर्ग की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बीड-अहिल्यानगर-मुंबई और बीड-अहिल्यानगर-पुणे मार्गों पर प्रतिदिन चलने वाली इंटरसिटी रेल्वे सेवाएं शुरू करने की भी मांग की गई। इन सेवाओं से मराठवाड़ा	का संपर्क राज्य के प्रमुख शहरों से सीधे और मजबूत होगा-इस पर विस्तार से चर्चा हुई। पूर्व बीड शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए बाशीं नाका (बीड) क्षेत्र में सुलभ स्थान पर नया रेल्वे स्टेशन बनाने की आवश्यकता भी बताई गई। सांसद सोनवणे ने कहा कि इस स्टेशन से यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी और बीड शहर के समग्र विकास को गति मिलेगी। साथ ही, अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वे मार्ग पर कई स्थानों पर रेल्वे फाटकों के कारण लगातार यातायात जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। इस जोखिम को कम करने के लिए संबंधित स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग भी रेल्वे मंत्री के समक्ष रखी गई। ----- गुटखा तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो... हिरासत में ले लिया। पंचों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी लेने पर अलग-अलग बोरियों में प्रतिबंधित 'हिरा' कंपनी का गुटखा पाया गया। पुलिस ने गुटखा और स्कॉर्पियो वाहन सहित कुल १३,७४,१४० रुपये का माल जब्त किया है। इस मामले में बीड ग्रामीण पुलिस थाने में लक्ष्मण राधाकिसन खांडे, कृष्णा घोडके और रोहित घोडके के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धाराओं १२३, २२३, २७४ और २७५ के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और आगे की जांच चल रही है। यह कार्रवाई उपअधीक्षक पूजा पवार के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक माधव काटकर और पुलिस हवलदार सचिन आगलावे ने की। ----- चीन सीमा पर क्या... दुर्घटना पर संदेह	सपकाल ने उपमुख्यमंत्री -क्षर्ळी झुरी की विमान दुर्घटना को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से पहले की अंतिम बातचीत वायरल हुई है, लेकिन अब तक ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की गई और न ही जांच में कोई टोस प्राप्ति दिख रही है। यह देरी समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ऋषिपवोर ऋवपरींळी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शपथविधि में जितनी तेजी दिखाई गई, उतनी तत्परता दुर्घटना की जांच में नहीं दिखी। सपकाल ने कहा कि जब तक इस दुर्घटना के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती, तब तक ऐसे सवाल उठते रहेंगे। इस हादसे ने कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ दिया है। ----- २०२९ में बीड का विधायक अनिल... कलाकारों के लिए अनिलदादा जगताप द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विशेष प्रशंसा की। शिवसेना जिलाप्रमुख -पळथ गरसींरि ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के कर्तव्यनिष्ठ उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे तथा संसद रत्न सांसद डहीळज़रपी डहळपवश के जन्मदिन के अवसर पर बीड के कला क्षेत्र को समृद्ध करने के उद्देश्य से चंपावती महोत्सव की शुरुआत की गई है। कला की विरासत को चंपावती महोत्सव के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ाने का हम सभी कलाकारों को आश्वासन देते हैं, उन्होंने कहा। कार्यक्रम के अंत में उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी मान्यवरों और कलाकारों का अनिलदादा जगताप ने आभार व्यक्त किया। चौकट चंपावती भूषण पुरस्कार से सम्मान चंपावती महोत्सव के उद्घाटन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय और प्रेरणादायी कार्य करने वाले मान्यवरों को 'चंपावती भूषण पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।	डॉ. विनिता ढाकणे - शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रणिता गंगाखेडकर (शिक्षा विस्तार अधिकारी) - जिला परिषद स्कूल के आदर्श कार्य के लिए शेख अज़हर - खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नितिन कोटेचा - उद्यमिता एवं सामाजिक क्षेत्र में आदर्श कार्य के लिए मनोज धस - - - - - शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ----- बीड शहर के लिए बिंदुसरा परियोजना... पूर्व नगरसेवक गणेश वाघमारे, रवी कदम, नगरसेवक सय्यद मुस्तफा, नगरसेविका मीना जाधव, समीक्षा शेठे, सावित्री साखरे, भाग्यश्री तांबारे, भाग्यश्री देशपांडे, अधिवक्ता नागेश तांबारे, विकास जोगदंड, संपादक साहस आंदोडे, अधिवक्ता गोविंद शिराळे, बालासाहेब गुजर, सागर देशपांडे, मंगेश धोंगडे, सनी माने, राकेश जाधव, नितिन साखरे, माणिक वाघमारे, विशाल राऊत सहित भाजपा के वर्तमान व पूर्व नगरसेवक एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चौकट मालमत्ता पंजीकरण अभियान के लिए विशेष निधि की मांग बीड शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है और नई संपत्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन सभी संपत्तियों का नगरपरिषद अभिलेखों में पंजीकरण आवश्यक होने के कारण व्यापक मालमत्ता पंजीकरण (असेसमेंट) अभियान के लिए विशेष निधि उपलब्ध कराने की मांग डॉ. सारिकाताई क्षीरसागर ने की। पंजीकरण पूरा होने से नगरपरिषद का राजस्व बढ़ेगा और शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो सकेगा। इस अभियान हेतु लगभग एक करोड़ रुपये की निधि देने की मांग की गई है। -----
--	--	---	--